भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4821

23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: ग्रामीण हाट का विकास

4821. श्री मितेश रमेशभाई पटेल (बकाभाई):

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में ग्रामीण हाटों को कृषि बाजारों के रूप में विकसित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गुजरात के आणंद और अन्य जिलों के ग्रामीण हाटों को कृषि बाजारों के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां कृषि बाजार विकसित किए जाने की संभावना है और ये कृषि बाजार कब तक विकसित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): जी, हां। केन्द्रीय बजट घोषणा पत्र 2018-19 के अनुसार सरकार ने मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि मंडियों (जीआरएएमएस) के रूप में विकसित करने और अद्यतन करने की घोषणा की है। इन जीआरएएमएस में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और अन्य सरकारी योजनाओं के उपयोग से वास्तविक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। ये जीआरएएमएस इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-नाम से जोड़ी जाएगी और इन्हें एपीएमसी विनियमों से छूट प्रदान की जाएगी, किसानों को उपभोक्ता और थोक क्रेताओं को सीधे बिक्री करने की सुविधा प्रदान करेंगी।

सरकार ने इन जीआरएएमएस में बेहतर प्रबंधन करने की सुविधा प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों को जीआरएएमएस के प्रचालन और प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश परिचालित किए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 10,000 ग्रामीण हाटों तथा 585 कृषि उत्पाद मंडी समिति (एपीएमसी) मंडियों में कृषि विपणन अवसरंचना को विकसित करने तथा अपग्रेड करने के लिए नाबार्ड को 2000 करोड़ रूपये के कार्पस वाली एक कृषि मंडी अवसंरचना निधि (एएमआईएफ) का अनुमोदन किया है। ग्रामीण हाटों में आधारभूत अवसंरचना का विकास स्थानीय निकायों द्वारा उनकी आवश्यकता के आधार पर जिला अधिकारियों के साथ मिलकर मनरेगा के माध्यम से किया जाता है। गुजरात के आणंद और अन्य जिलों के स्थानीय निकाय अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत गुजरात के तीन ग्रामीण हाटों में विकास का कार्य शुरू कर दिया गया था।

****